शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

स्कूल खुलने की तारीख तय नहीं...

विभाग ने 15 जून को किताबें बांटने के जारी किए आदेश

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भोपाल

लॉकडाउन के चलते शैक्षणिक संस्थान बंद है। हालांकि इसके चौथे चरण में कुछ ढील मिलनी शुरू हुई है, लेकिन फिलहाल स्कूलों को खोलने को लेकर असमंजस है। जहां केंद्र सरकार स्कूलों को सुबह-शाम खोलने और स्टूडेंट्स को ऑड-ईवन के फॉर्मूले पर विचार कर रही है वहीं राज्य सरकार के आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग इस शैक्षणिक सत्र में स्कूल चलाने को लेकर स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तैयार कर रही है। इस बीच राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश ने प्रदेश भर के शिक्षकों को परेशानी में डाल दिया है। राज्य शिक्षा केन्द्र से जारी एक आदेश में 15 जून को छात्रों को समारोह पूर्वक किताबें बांटने का आदेश दिया है। कोरोना के मरीज बढ़ने की संभावना के बीच इस आदेश को लेकर प्रदेशभर के शिक्षक टेंशन में हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी मानते हैं कि पाठ्यपुस्तक वितरण का आदेश हर साल जारी होता था। संभवतः इसी के चलते ये चूक हुई है।

स्कूल खुलने पर ही मिलेगी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को किताबें

15 जून को समारोह पूर्वक किताबें वितरण के है आदेश

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को किताबें स्कूल खुलने पर ही मिलेगी। जबकि राज्य शिक्षा केंद्र ने पूर्व में पंद्रह जून को समारोह पूर्वक किताबों के वितरण करने के आदेश निकाले थे। कोरोना संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ढाई महीने पहले प्रदेश भर में स्कूल बंद कर दिए गए थे। दो महीने बाद लॉक डाउन के चौथे चरण में कुछ ढील मिलनी शुरू हुई है। लेकिन स्कूलों के शुरू किए जाने को लेकर अभी फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने तीन तिथियों में स्कूल खोलने का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। यह पंद्रह जुलाई, एक अगस्त व पंद्रह अगस्त है। लेकिन स्कूल पूर्व एक मई को राज्य शिक्षा केंद्र ने पंद्रह जून को समारोह पूर्वक विद्यार्थियों को किताब वितरण करने के आदेश जारी किए थे। कोरोना के मरीज बढ़ने की संभावना के बीच इस आदेश को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक टेंशन में हैं। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त लोकेश जाटव का कहना है पूर्व में किताब वितरण के आदेश सात जून तक की छुट्टियों को देखते हुए निकाले गए थे। किताबों का वितरण स्कूल खुलने पर ही किया जाएगा। जल्द ही इस संबंध में नए निर्देश जारी किए जाएंगे।

शिक्षकों को खुश रहने के लिए सरकार ने तैयार करवाए कोर्स

इंदौर • डीबी स्टार

स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के शिक्षकों को खुश रहने के गुर सिखाएगा। इसके लिए राज्य आनंद संस्थान ने अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिल्लमेंट (अलोह्म) ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। डीपीआई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है।

प्रदेश के शिक्षक, प्राचार्य और अफसर लॉकडाउन में घर बैठे खुश रहने के तरीके सीख सकेंगे। इस दौरान उन्हें यह सिखाया जाएगा कि सुखी और संपन्न जीवन के मूल में क्या है? लोक शिक्षण संचालनालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस कोर्स में भोपाल जिले के 200 और राजगढ़ जिले के 100 शिक्षकों को ऑनलाइन कोर्स में शामिल किया था। उनसे मिली प्रतिक्रिया से विभाग उत्साहित है। इसलिए अफसर चाहते हैं कि विभाग के बाकी शिक्षक, प्राचार्य और अफसर भी इस कोर्स का फायदा उठाएं।

एचआरडी मंत्री का लाइव सेशन में बड़ा एलान

कॉलेज के विद्यार्थियों को भी मिलेगा प्रमोशन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि फाइनल ईयर या अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी, जैसा की यूजीसी ने घोषणा की है। यदि कुछ स्थानों पर स्थिति में सुधार नहीं होता तो ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। वहीं अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। इनके प्रमोशन का आधार पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा। यानि इन बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। उन्होंने इसे चुनौती को अवसर में बदलने वाला समय बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार है और जल्द ही इसे संसद से पास कराकर लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. निशंक ने देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 45000 उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की कि कोविड 19 के इस चुनौती भरे समय को हम कैसे बदल सकते हैं।

प्रमोशन का आधार पुराना एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा। यानी इन बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा।

लॉकडाउन डायरी प्रतियोगिता में जिला शिक्षा केन्द्र को मिला द्वितीय स्थान

दतिया ब्यूरो। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा आयोजित प्रथम चरण की प्रतियोगिता 'लॉकडाउन डायरी' में सर्वाधिक प्रतिभागिता के लिए जिला शिक्षा केन्द्र दतिया को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलबिध पर जिला परियोजना समन्वयक अशोक त्रिपाठी ने बीआरसीसी दतिया राजेश शुक्ला, सेंवढ़ा के पुरुषोत्तम पाठक, भाण्डेर के मनीष सेन सहित सभी बीएसी व सीएसी सहित शिक्षकों व बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री त्रिपाठी ने कहा कि अब हमें 'पीढ़ियों का ज्ञान' विषय पर बच्चों के नाना-नानी, दादा-दादी, ताऊ-ताई के अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर जिले को नम्बर एक बनाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें सर्वाधिक प्रविष्टि प्राप्त करने हेतु दतिया विकासखण्ड के लिए आलोक गोस्वामी, सेंवढ़ा के पुष्पराज सिंह, भाण्डेर के रामनिवास त्रिपाठी को प्रतियोगिता प्रभारी महेन्द्र शर्मा के सहयोग से अधिकृत किया गया है।

कार्यालयों में कर्मचारियों को स्वस्थ्य रखने अफसरों ने अपनाए नए तरीके

राज्य ओपन में कर्मचारियों को आयुर्वेद का काढ़ा पीकर रजिस्टर में करने होंगे हस्ताक्षर

ऑफिस में आते और जाते वक्त सेवकों के लिए यह व्यवस्था की गई है अनिवार्य

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों को स्वस्थ रखने के लिए अफसरों ने नया तरीका निकाला है। शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा परिषद यानी राज्य ओपन कार्यालय से हुई है। यहां पर हर कर्मचारी को प्रतिदिन दो टाइम आयुर्वेद काढ़ा पीना अनिवार्य किया गया है।

राज्य ओपन महामारी के बीच में प्रदेश का एकलौता शासकीय कार्यालय है। जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यहां पर हर दिन कर्मचारी को ऑफिस आते वक्त एवं छुट्टी के टाइम आयुर्वेद काढ़ा पीना होगा। इसकी बाकायदा इंट्री भी रजिस्टर में होगी। कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं की उन्हें यह दवा पीकर रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हुए लिखना होगा कि उन्होंने दोनों टाइम इस औषधि का सेवन किया है। 2 सप्ताह पूर्व यह व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं।

आयुर्वेद काढ़ा पीना हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य: राज तिवारी

ओपन के संचालक पंडित प्रभात राज तिवारी का कहना है कि कार्यालय में यह दवा पीना अकेले कर्मचारियों के लिए ही नहीं सभी शाखा अधिकारियों के लिए भी अनिवार्य की गई है। वह स्वयं दोनों टाइम आयुर्वेद दवा पी रहे हैं। सरकार के निर्देश है इस कारण उसका पालन करना हम सभी का दायित्व है। श्री तिवारी के अनुसार यही प्रयास है कि हमारे ऑफिस का प्रत्येक कर्मचारी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। अगर यह दोनों फायदे हमें हुए तो यह कार्यालय के लिए बड़े गौरव और राहत की बात होगी। श्री तिवारी का कहना है कि ऑफिस के बाहर पानी और साबुन की व्यवस्था की गई है। ऑफिस के अंदर प्रवेश करते ही प्रत्येक कर्मचारी को साबुन से हाथ धोना होगा। उसके बाद ही उसे कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।

हर कार्यालय करें इस प्रयोग का अनुसरण: प्रमोद तिवारी

स्वास्थ विभाग के सेवक एवं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी का कहना है कि प्रदेश के प्रत्येक सरकारी कार्यालय को इस प्रकार के प्रयोग का अनुसरण करना चाहिए। श्री तिवारी का कहना है कि इसके लिए ओपन की तरह हर कार्यालय में सक्षम अफसरों को सख्ती बरतनी होगी। पहले उन्हें स्वयं दवा पीने की शुरुआत करना चाहिए। इसके बाद वह समस्त कर्मचारियों को निर्देशित कर दवा का सेवन अनिवार्य करें। तिवारी कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो किसी भी कर्मचारी के समक्ष कोरोना महामारी आ ही नहीं सकती है। इसके लिए जहां दवा जितनी जरूरी है। उससे कहीं अधिक आवश्यकता जागरूक रहने की है।

आयुर्वेद दवा बीमारी भगाने में है सहायक: श्रीवास्तव

क्लास 3 में शिक्षा समिति संयोजक अरविंद भूषण श्रीवास्तव का कहना है कि आयुर्वेद का काढ़ा बीमारी को भगाने में पूरी तरह सहायक है। पर यह तब संभव है जब इसका नियमित रूप से सेवन किया जाए। श्री श्रीवास्तव का कहना है कि राज्य ओपन में यह एक स्वास्थ्य की दृष्टि से अभिनव प्रयोग हुआ है। जाहिर तौर पर अगर सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों में इस प्रकार की शुरुआत हो जाए तो निश्चित ही हम आसानी से महामारी पर विजय पा सकते हैं। इसमें लोगों को अपनी इच्छा शक्ति को भी जागृत करना होगा।

कोराना से मुक्ति के लिए बांट रहे वन औषधीय युक्त हवन सामग्री

भोपाल (आरएनएन)। अखिल विश्व गायत्री परिवार भोपाल गायत्री जयंती की पूर्व बेला 31 मई को गृह गृह गायत्री यज्ञ की विस्तृत कार्ययोजना बनाई । भोपाल को 12 जोनों में बांटा, 12 जोनों को 52 उपजोनों में बांटा और 52 उपजोनों को 20- 20 कॉलोनियों का जिम्मा दिया प्रत्येक कॉलोनी में पूर्ण यज्ञ 24 घरों में और संक्षिप्त और वैकल्पिक यज्ञ 30 घरों में करने का लक्ष्य निर्धारण किया है। इस प्रकार पूर्ण यज्ञ औषधियुक्त कोराना मुक्ति मंत्र के साथ में 24000 घरों और इतने ही घरों में संक्षिप्त ओर वैकल्पिक यज्ञ के माध्यम से हम नए लोगों तक यज्ञ को पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम भोपाल में 51000 घरों में पहुंचेंगे, सभी सक्रिय परिजन भाई बहनों ने कमर कस ली हैअपने कालोनियों। बनऔषधीय युक्त हवन सामग्री लेकर वितरित करते हुए पंजीयन कर रहे है। साथ मे संपन्न कराने और प्रचार करने के नए-नए तरीके सोसल मीडिया द्वारा जैसे मोबाइल पंडित, ऑनलाइन ,फोन लगा, यज्ञ करने का यस और नो का ऑप्शन डालकर आदि शासन के नियमों का पालन करते हुए अभी तक सूची बनाने वालों में संध्या जैन अकेले 400 परिजनों अरेरा कॉलोनी क्षेत्र, शोभा रस्तोगी ने 145 कटारा हिल्स, अंजना परिहार 200, पीके गुप्ता 80 मिनाल रेसीडेंसी ,देवयानी लोखंडे 175 अटलांटा इसी प्रकार अनेक भाई बहनों ने अपने-अपने कॉलोनी की सूची बनाई है । सूची बनाते समय फोन करते समय उनको पूरी सलाह दी जा रही है कि आप अपने घर में रहकर ही स्वयं के घर की सामग्री या हो सके तो गायत्री परिवार की ओषधीय युक्त हवन सामग्री मिल जाए तो आप उससे यज्ञ करें यदि सामग्री नहीं तो वैकल्पिक यज्ञ अपने घरों में मौजूद गुड़ , घी,चावल, तिल ,नीम आम, पीपल, गिलोय के पत्ते, घरेलू मसाले दालचीनी, लोंग, तेपत्र आदि का मिश्रण मिलाकर यज्ञ अवश्य करें।

हॉटस्पॉट क्षेत्र के चार परीक्षा केंद्रों में होगा परिवर्तन

बैठक में केंद्र अध्यक्षों से पूरा फीडबैक लेने के बाद कलेक्टर को भेजा प्रस्ताव

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

अगले माह से 12वीं के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा कराने जा रहा माध्यमिक शिक्षा मंडल राजधानी के चार परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन करेगा। यह ऐसे केंद्र हैं जो हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आते हैं। गुरुवार को केंद्र अध्यक्षों की बैठक लेने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने यह निर्णय लिया है।

यह बैठक शिवाजी नगर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित की गई थी। इसमें समस्त परीक्षा सेंटर के केंद्र अध्यक्षों को बुलाया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह बैठक 4 कक्ष में आयोजित की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया की राजधानी में 4 परीक्षा केंद्र ऐसे हे जहां पर मौजूदा समय में बच्चों की परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। उन्होंने बताया है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद महाराणा प्रताप एवं आनंद विद्या मंदिर सहित एक अन्य स्कूल है जहां पूर्व से ही सेंटर थे। यह पूरा इलाका हॉटस्पॉट क्षेत्र में है।

नतीजतन प्राचार्य से मशविरा कर यहां पर परीक्षा ना कराने का निर्णय बैठक में हुआ है। उन्होंने कहा है कि इन केंद्रों को बदलने के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही प्रशासन का अनुमोदन मिलेगा तो तत्काल इन चारों परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन किया जाएगा। इसके लिए ऐसे क्षेत्रों के स्कूल चिन्हित होंगे जहां पर आपदा का प्रकोप नहीं है। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मंडल की जो गाइडलाइन है। उसी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 9 जून से प्रारंभ होने वाली परीक्षाएं कराएंगे।

80 स्कूलों में वितरित राशन तराजू ना होने से परेशानी

शासन के निर्देश पर गुरुवार से सरकारी स्कूलों में प्रारंभ हुए राशन का वितरण करने में शिक्षकों और स्व सहायता समूह को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कारण है कि प्रति बच्चे के मान से तराजू पर तोलते हुए राशन दिया जाना था। समस्या यह रही कि स्कूलों में तराजू और बांट ना होने के कारण दिक्कतों का सामना हुआ। कई शिक्षकों ने तो ग्रामीणों से मदद स्वरूप तराजू लिया लेकिन कई जगह यह व्यवस्था नहीं हो पाई। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि पहले दिन 80 स्कूलों में राशन का वितरण कराया गया। उन्होंने कहा है कि यह व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्व सहायता समूहों की थी। अगर कोई यह समस्या लेकर उनके पास आता है तो उसका समाधान किया जाएगा।

शिक्षकों को योद्धा का दर्जा तत्काल दे सरकार

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौड़ ने सरकार से मांग की है कि वह तत्काल प्रदेश के शिक्षकों को योद्धा का दर्जा घोषित करें। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया है। महामंत्री क्षेत्र वीर ने बताया कि शिक्षक इस समय काम का दोहरा दबाव झेल रहा है। अपने मुख्य काम के साथ शिक्षक कोरोना ड्यूटी भी कर रहा है। इस कारण शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए।

नीट परीक्षा केंद्र बढ़ाने की मांग

भोपाल। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट (नीट) के माध्यम से प्रदेश समेत देशभर के मेडिकल, डेंटल, आयुष कॉलेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए 26 जुलाई को परीक्षा देशभर के 155 शहरों में 2546 केंद्रों पर आयोजित होगी परंतु कोविड -19 कोरोना के चलते बढ़ रहे मरीजों की संख्या व लॉकडाउन के कारण बस, ट्रेन व सभी संसाधन प्रारंभ न होने के कारण प्रदेश के चालीस हजार समेत देशभर के 6 लाख से ज्यादा छात्र नीट में शामिल होने से वंचित रह सकते हैं, ऐसा आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पाण्डेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मांग की है कि मध्यप्रदेश समेत देशभर में परीक्षा सेंटर्स बढ़ाए जाएं। देशभर के प्रत्येक जिले में नीट परीक्षा सेंटर बनाया जावे, अन्यथा 6 लाख से ज्यादा आवेदक छात्र परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं

शिक्षक कांग्रेस की मांग, अन्य कर्मचारियों की तरह मिलें सुविधाएं

भोपाल। मप्र शिक्षक कांग्रेस ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर 12वीं के शेष पेपरों की परीक्षा जुलाई माह में कराने सहित शिक्षकों को कोरोना योद्धा योजना में शामिल करने की मांग की है। शिक्षक कांग्रेस का कहना है कि देश में दो लाख शिक्षकों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जा रही है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अर्जित अवकाश प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को जहां नहीं दिया जा रहा है, वहीं हाईस्कूल और हाई सेकंडरी के प्रधानों को अध्यापकों को अर्जित अवकाश दिया जा रहा है। सक्सेना ने कहा कि प्रदेश के दूसरे कर्मचारियों की तरह ही शिक्षक कर्मियों को भी कोरोना योद्धा मानते हुए उनको वह सुविधाएं दी जाना चाहिए जो सफाई कर्मी स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को दी जा रही है।

9 से 16 जून के मध्य होगी हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं

अनूपपुर। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हायर सेकंडरी की परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 9 से 16 जून के मध्य किया जाएगा। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक तैयारियों के सम्बंध में भी निर्देश दिए गए हैं। जारी निदेशों के अनुसार केन्द्र पर सभी छात्रों को अपने नाक, मुंह को नकाबध्कपडे से ढक कर रखना एवं फिजिकल डिस्टेन्स का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिये उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेगें कि, उनके बच्चे बीमार नही हो।

परीक्षा केंद्रो में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए होंगी आवश्यक व्यवस्थाएं

सभी निर्देशों का कडाई से करना होगा पालन

परीक्षा केन्द्रों पर उपस्थित होने के दौरान जारी किये गये सभी निदेशों का कडाई से पालन किया जायेगा। परीक्षार्थी एवं अन्य सर्वसंबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भलीभाँति नोट कर लें। परीक्षाकाल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो भी परीक्षायें यथावत कार्यक्रमानुसार सम्पन्न होगी।

शेष प्रायोगिक परीक्षा 9 से 16 जून तक

स्वाध्यायी छात्रों की शेष प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित परीक्षा केन्द्र में 9 से 16 जून तक आयोजित की जायेगी। उनकी तिथियां तथा समय ज्ञात करने के लिये प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष से संपर्क स्थापित रखा जावे। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों मे भी आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा केन्द्र पर समस्त परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जावेगी। मण्डल आवश्यकता होने पर तिथि एवं समय मे कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है किन्तु संचार माध्यमों से सूचना करेगा। हायर सेकेण्डरी परीक्षा मे केवल वाणिज्य संकाय के विषयों को छोडकर शेष विषयों मे नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिये प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा, किन्तु नियमित छात्रों को 100 अंक के प्राप्तांक का 80 प्रतिशत अधिभार एवं स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक ही अंकसूची मे प्रदर्शित किये जायेगें।

कक्षा बारहवीं की परीक्षा की संशोधित समय सारिणी जारी

माध्यमिक शिक्षा मंडल की बारहवीं कक्षा की शेष परीक्षाएं 9 से 16 जून के बीच होंगी माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने बारहवीं कक्षा की संशोधित समय सारिणी जारी की है। परीक्षा 9 से 16 जून के बीच ही होंगी, विषयवार तिथि में बदलाव किया गया है। 9 जून को पहली पाली में सुबह 9 से 12 दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर होगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अनूपपुर ने बताया कि 9 जून को प्रथम पाली में 9 से 12 बजे तक केमिस्ट्री तथा दूसरी पाली 2 से 5 बजे तक भूगोल विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 10 जून को प्रथम पाली में 9 से 12 बजे तक बुक कीपिंग एवं एकाउंटेंसी, तथा द्वितीय पाली में 2 से 5 बजे तक प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स, 11 जून को 9 से 12 बजे तक बायोलाजी, 12 जून को 9 से 12 बजे तक व्यावसायिक अर्थशास्त्र तथा 2 से 5 बजे तक एनिमल हस्बेण्ड्री मिल्कट्रेड पोल्ट्री फार्मिंग एण्ड फिसरीज की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी तरह 13 जून को 9 से 12 बजे तक राजनीति शास्त्र, 2 से 5 बजे तक शरीर रचना क्रिया- विज्ञान एवं स्वास्थ्य, स्टिल लाईफ एण्ड डिजाईन, द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स तथा 15 जून को 9 से 12 बजे तक हायर मैथमैटिक्स तथा 2 से 5 बजे तक विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 16 जून को 9 से 12 बजे तक अर्थशास्त्र तथा 2 से 5 बजे तक क्रॉप प्रोडक्शन एवं हॉर्टिकल्चर विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

दस उपकोषालय बंद किये गये, राज्य के वित्त विभाग ने जारी किये आदेश

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार ने दस उपकोषालयों को बंद कर दिया है। ये उपकोषालय हैं : शाहपुर जिला बैतूल, तेंदूखेड़ा जिला दमोह, सेगांव जिला खरगौन, नैनपुर जिला मण्डला, पवई जिला पन्ना, सैलाना जिला रतलाम, रामपुर बघेलान जिला सतना, चितरंगी जिला सिंगरौली, नागदा जिला उज्जैन तथा ग्यारसपुर जिला विदिशा।उक्त संबंध में राज्य के वित्त विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश में कहा गया है कि उक्त उपकोषालयों में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 एवं भृत्य के 19 पद संबंधित जिला कोषालयों की स्थापना में समर्पित किये जायेंगे और बहुमूल्य संपत्तियों/मुद्रांकों के पैकेट्स को भी संबंधित जिला कोषालयों के सुरक्षित कक्षों में स्थानांतरित किये जायेंगे।

फिजिकल डिस्टेंसिग के तहत परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश

सतना। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक परीक्षा वर्ष 2020 (सामान्य/दिव्यांग छात्र) की शेष बची परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षायें 9 जून से 16 जून 2020 तक पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित कराये जाने के निर्देश है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री टीपी सिंह द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रो पर फिजिकल डिस्टेंन्सिंग के तहत परीक्षायें आयोजित कराये जाने के निर्देश जारी किये गये है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्रो को सेनेटाईज किया जावेगा। परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्रो को अपने नाक, मुंह को नकाब/कपड़े से ढक कर रखना एवं फिजिकल डिस्टेन्स नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जायें। केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा केन्द्रों में छात्रो के साबुन से हाथ धुलाने एवं हैण्ड सेनेटाईजेशन की व्यवस्था की जावेगी। परीक्षा केन्द्रो पर समस्त परीक्षार्थियों थर्मल स्क्रीनिंग की जावेगी। समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अभिभावक अपने बच्चो को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देगे तथा जागरूक करें ताकि बच्चे किसी प्रकार के संक्रमण से बचे रहें। परीक्षा केन्द्रो पर उपस्थित होने के दौरान मंडल द्वारा जारी किये गए सभी निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जायेगा। परीक्षार्थी एवं सर्वसंबंधित परीक्षा कार्यक्रम को भलीभांति नोट कर लें। परीक्षाकाल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो परीक्षायें यथावत मंडल द्वारा जारी परीक्षा समय सारणी अनुसार सम्पन्न होगी। प्रतिदिन थाना एवं परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्न-पत्र के लिफाफे निकालने एवं खोलने की प्रक्रिया मंडल के निर्देशानुसार पूर्ण करेगें।

10वीं और 12वीं का मूल्यांकन हुआ पूरा, ओएमआर शीट भोपाल रवाना

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर| जबलपुर जिले में 10वीं और 12वीं की 2.47 लाख उत्तरपुस्तिकाओं का प्रथम चरण का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। गुरुवार को ओएमआर शीट भोपाल रवाना कर दी गई है। इससे 10वीं का रिजल्ट जल्द खुलने की संभावना बन गई है, जबकि 12वीं के शेष पेपर 9 से 15 जून के बीच आयोजित किए जाएँगे। एमएलबी स्कूल के प्राचार्य अतुल खंडेलवाल ने बताया कि जबलपुर में चार जिलों से 10वीं की 1.5 लाख और 12वीं की 97 हजार उत्तरपुस्तिकाएँ भेजी गई थीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 29 मई तक मूल्यांकन कार्य करने का निर्देश दिया था। लॉकडाउन की वजह से शिक्षकों से उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन घर से कराया गया।

व्यवस्था • रादुविवि में बनेंगे 20 नए परीक्षा केन्द्र, बरतेंगे सोशल डिस्टेंसिंग

परीक्षा केन्द्रों में तैनात होगी स्वास्थ्य विभाग की टीम, संदिग्ध छात्रों को अलग बैठाया जाएगा

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

अगले महीने से होने वाली विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के परीक्षा केन्द्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में यदि किसी छात्र को संदिग्ध पाया जाता है तो उन्हें अलग बैठाकर परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के दौरान हर छात्र को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने यह जानकारी प्रदेश के कुलपतियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी है। रादुविवि के कुलपति प्रो. कपिलदेव मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि वर्तमान में रादुविवि में 71 परीक्षा केन्द्र हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए 20 नए परीक्षा केन्द्र बनाए जा रहे हैं। परीक्षा के पहले और बाद में परीक्षा केन्द्रों का सेनिटाइजेशन कराया जाएगा। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी।

आत्मनिर्भरता पर वेबिनार आज

रादुविवि प्रबंधन संस्थान द्वारा 29 मई को आत्मनिर्भरताः अवधारणा एवं साध्यता विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। वेबिनार में प्रतिभागियों द्वारा पंजीयन उपरांत प्रधानमंत्री राहत कोष में 101 रुपए दान करने पर ई प्रमाण पत्र प्रदान करने का निश्चय किया गया है।

कॉलेजों में जनरल प्रमोशन देने की माँग

एनएसयूआई ने गुरुवार को कॉलेजों में जनरल प्रमोशन और स्कूलों में फीस माफी की माँग को लेकर राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में अगले माह से कॉलेजों में परीक्षा कराने का आदेश दिया गया है, लेकिन कोरोना को देखते हुए परीक्षा कराने से महामारी का खतरा बढ़ेगा। एनएसयूआई ने निजी स्कूलों में तीन माह की फीस माफ करने की भी माँग की है। ज्ञापन देने वालों में कपिल भोजक, बादल पंजवानी, राहुल रजक और रोहित रैकवार शामिल थे। पी-4

विद्यार्थियों पर फीस देने का दबाव नहीं डालने के निर्देश

यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन, हालात को देखते हुए बरतें सहानुभूति

कार्यालय संवाददाता | रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालयों की ओर से विद्यार्थियों पर फीस को लेकर डाले जा रहे दबाव से विद्यार्थी और उनके अभिभावक परेशान हैं। लेकिन अब उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा क्षेत्र के नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विद्यार्थियों पर फीस देने का दबाव नहीं डालने के निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी ने कहा है कि हालात को देखते हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति बरतनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों को तुरंत फीस देने के लिए बाध्य नहीं करें और व्यक्तिगत मामलों को सहानुभूति पूर्वक देखें। विश्वविद्यालय के कुलपति और महाविद्यालय

के प्राचार्यों को लिखे पत्र में यूजीसी ने कहा है कि उन तक विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से शिकायत मिली है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज वार्षिक, सेमेस्टर, ट्यूशन शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि के तत्काल भुगतान पर जोर दे रहे हैं।

विद्यार्थियों ने पहल का किया स्वागत

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से जारी हुए पत्र का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे वित्तीय संकट की स्थिति में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रबंधन से इस पर अमल करने के लिए कहा है।

छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि यूजीसी का यह कदम सराहनीय है और मानव संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस निर्णय के कारण मुख्य रूप से निर्धन तबके के विद्यार्थियों और अभिभावकों को काफी सहायता मिल सकेगी।

लॉकडाउन के कारण वित्तीय कठिनाई

यूजीसी को लिखे पत्र में विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण उन्हे वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे में वह फीस भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। यूजीसी ने इसे स्वीकारते हुए कहा है कि मौजूदा असाधारण कठिन परिस्थितियों के मद्देनजर विश्वविद्यालय और कॉलेज वार्षिक, सेमेस्टर शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि के भुगतान के संबंध में कठिन समय को देखते हुए विचार कर सकते हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। वहीं यदि संभव हो तो विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक भुगतान की पेशकश करने पर भी विचार कर सकते हैं।

विद्यार्थियों पर फीस देने का दबाव नहीं डालने के निर्देश

यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन, हालात को देखते हुए बरतें सहानुभूति

कार्यालय संवाददाता | रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालयों की ओर से विद्यार्थियों पर फीस को लेकर डाले जा रहे दबाव से विद्यार्थी और उनके अभिभावक परेशान हैं। लेकिन अब उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा क्षेत्र के नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विद्यार्थियों पर फीस देने का दबाव नहीं डालने के निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी ने कहा है कि हालात को देखते हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति बरतनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों को तुरंत फीस देने के लिए बाध्य नहीं करें और व्यक्तिगत मामलों को सहानुभूति पूर्वक देखें। विश्वविद्यालय के कुलपति और महाविद्यालय

के प्राचार्यों को लिखे पत्र में यूजीसी ने कहा है कि उन तक विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से शिकायत मिली है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज वार्षिक, सेमेस्टर, ट्यूशन शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि के तत्काल भुगतान पर जोर दे रहे हैं।

विद्यार्थियों ने पहल का किया स्वागत

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से जारी हुए पत्र का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे वित्तीय संकट की स्थिति में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रबंधन से इस पर अमल करने के लिए कहा है।

छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि यूजीसी का यह कदम सराहनीय है और मानव संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस निर्णय के कारण मुख्य रूप से निर्धन तबके के विद्यार्थियों और अभिभावकों को काफी सहायता मिल सकेगी।

लॉकडाउन के कारण वित्तीय कठिनाई

यूजीसी को लिखे पत्र में विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण उन्हे वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे में वह फीस भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। यूजीसी ने इसे स्वीकारते हुए कहा है कि मौजूदा असाधारण कठिन परिस्थितियों के मद्देनजर विश्वविद्यालय और कॉलेज वार्षिक, सेमेस्टर शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि के भुगतान के संबंध में कठिन समय को देखते हुए विचार कर सकते हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। वहीं यदि संभव हो तो विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक भुगतान की पेशकश करने पर भी विचार कर सकते हैं।

स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नात्कोत्तर की परीक्षाएं 29 जून से प्रारंभ

जागरण सिटी रिपोर्टर । प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों की स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाओं की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित होंगी। 29 जून से 31 जुलाई के मध्य पेन पेपर मोड पर परीक्षा केंद्रों पर जाकर विद्यार्थियों को परीक्षा देना होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा सभी शासकीय, अशासकीय स्वशासी, अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को परीक्षाओं एवं अकादमी कैलेंडर के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन में परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर और अन्य पाठ्यक्रमों की नियमित परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर परिस्थितियां सामान्य होने पर आयोजित की जा सकेंगी। स्नातक कक्षाओं के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रवेश देकर एक सितंबर 2020 से नया सत्र प्रारंभ किया जाएगा। इस वर्ष के लिए स्नातक कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नया सत्र 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा।

पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को दिया जाएगा अगली कक्षा में प्रवेश

कॉलेजों का नया शैक्षणिक सत्र 1 अक्टूबर से

स्टार समाचार | सतना

कोरोना महामारी ने उच्च शिक्षा विभाग की सारी योजनाओं को अव्यवस्थित कर दिया। जहां शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होता था वह अब 1 अक्टूबर से शुरू हो पाएगा। बिना परीक्षा दिए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा और परिस्थितियां सामान्य होने के बाद परीक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष एवं चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा 29 जून से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित होंगी।

यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए लिया है। बताया गया है कि 25 मई को आयोजित बैठक के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजी परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं में कई बदलाव किए गए हैं।

बताया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी पारंपरिक तथा निजी विश्वविद्यालयों की स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाओं की परीक्षाएं 29 जून से लेकर 1 जुलाई के दरमियान ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएंगी। यानी कि विद्यार्थियों को पारंपरिक तरीके से ही परीक्षा देनी है। ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी।

परिस्थितियां सामान्य होने के बाद होगी पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा

उच्च शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि स्नातक कक्षाओं में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष या सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश देकर एक सितम्बर से नया सत्र शुरू कर दिया जाए मगर जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर तथा अन्य पाठ्यक्रमों की नियमित परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी।

तीन महीने देरी से शुरू होगा नया सत्र

उच्च शिक्षा विभाग में नया शैक्षणिक सत्र आमतौर पर 1 जुलाई से प्रारंभ होता है मगर एडमीशन प्रक्रिया अगस्त तक चलती है। परंतु कोरोना महामारी के चलते 1 अक्टूबर से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने का निर्णय उच्च शिक्षा विभाग ने लिया है। जाहिर है कि पहले बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आएंगे और उसके बाद ही एडमीशन प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें कम से कम एक से डेढ़ महीने का वक्त लगेगा। जिसमें सितम्बर महीना ऐसे ही बीत जाएगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से पहले सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होंगी।

अगस्त तक आ जाएगा रिजल्ट

उच्च शिक्षा विभाग इस कवायद में लगा है कि 31 जुलाई तक आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएं। ताकि अगस्त महीने तक परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो जाएं और स्नातकोत्तर में सितम्बर महीने से एडमीशन प्रक्रिया शुरू हो सके।

पढ़ाई में जनरल प्रमोशन भविष्य के लिए बदनुमा दाग से कम नहीं

युनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में इसका कोई प्रोविजन नहीं

भास्कर न्यूज | सतना

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल-कॉलेज भी बंद हैं। ऐसे में कई छात्र संगठन डिग्री में जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं जबकि जानकारों का दावा है कि डिग्री में जनरल प्रमोशन भविष्य के लिए बदनुमा दाग से कम नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि युनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में जनरल प्रमोशन का कोई प्रोविजन नहीं है। इन्हीं जानकारों के मुताबिक कक्षा 1 से लेकर 12वीं और ग्रेजुएशन एवं मास्टर्स की डिग्री के बीच एक बड़ा अंतर बताया है। उन्होंने कहा कि दसवीं की अंकसूची जन्मतिथि के लिए, बारहवीं की अंकसूची सब्जेक्ट सेलेक्ट करने तथा ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की अंकसूची भविष्य बनाने के लिए उपयोग में आती है।

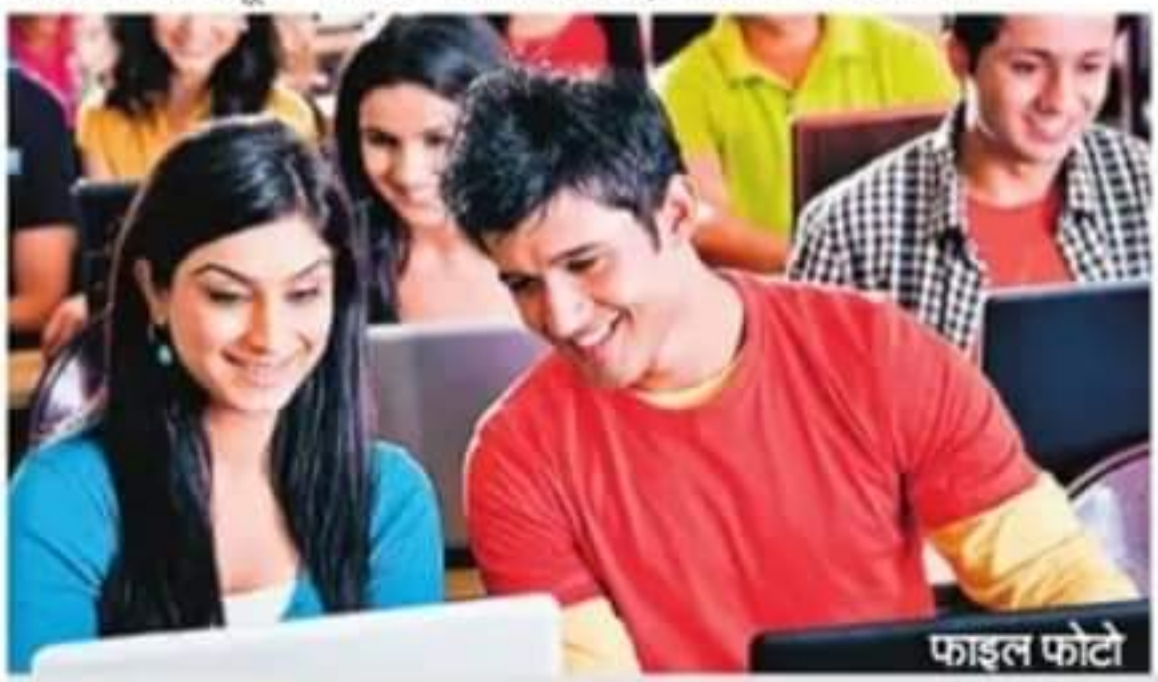

फाइल फोटो

जनरल प्रमोशन पर मार्कशीट में नहीं होंगे अंक

जानकारों ने जानकारी दी कि जनरल प्रमोशन से उत्तीर्ण छात्र अथवा छात्राओं की अंकसूची में अंक की जगह जनरल प्रमोशन लिखा जाएगा। यानि अंकसूची में हमेशा के लिए एक स्टेगमा लगा रहेगा। एक बड़ा सवाल ये भी है कि ग्रेजुएशन एवं मास्टर डिग्री के अंतिम सेमेस्टर या वर्ष की अंकसूची में जनरल प्रमोशन के अंक जोड़े जाएंगे। जबकि विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में जनरल प्रमोशन का कोई प्रोविजन नहीं है।

पढ़ाई से लेकर नौकरी तक पर असर

जानकारों ने अंदेशा जाहिर किया कि देश-विदेश के तकरीबन सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा के आधार पर ही छात्र-छात्रा को अगली कक्षाओं में भेजा जाता है। प्रमोटेड छात्र स्वयं ही दूसरे विश्वविद्यालयों की तुलना में दोयम दर्जे के हो जाएंगे। इसका सीधा असर विद्यार्थी के आगे की पढ़ाई एवं नौकरी पर जीवन पर्यंत पड़ेगा। अगर विश्वविद्यालय स्वयं अपने छात्र-छात्राओं का अपने हिसाब से मूल्यांकन करेंगे तो विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार का प्रश्नचिन्ह नहीं लगेगा।

लॉकडाउन से पहले सेलेबस पूरा

कालेजों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि लाकडाउन प्रारंभ होने के पहले ही 15 मार्च तक वार्षिक पाठ्यक्रमों का सेलेबस पूरा हो चुका था एवं परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली थीं। इसी प्रकार सेमेस्टर पैटर्न वाले पाठ्यक्रमों का सेलेबस भी लगभग आधा हो चुका था बाकी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के दिशा निर्देश पर प्रारंभ की थी। अब यदि कोई विद्यार्थी मार्च तक कोई भी दिन क्लास न आया हो यह अलग बात है।

उस दौर में भी नहीं मिला था प्रमोशन

सूत्रों ने बताया कि वर्ष 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, दंगे हुए एवं भोपाल गैस कांड हुआ था और पढ़ाई लगभग 6 से 8 माह तक प्रभावित थी तब भी बोर्ड परीक्षाओं एवं कॉलेजों में कोई जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया था। 1984 में जिन कक्षाओं के छात्रों को जनरल प्रमोशन मिला था वह अपनी कोई मार्कशीट आगे कभी प्रस्तुत नहीं कर पाए। जानकारों ने आशंका जाहिर की कि जनरल प्रमोशन देना लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ करना है।

DB STAR EXCLUSIVE प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना में हर माह 3500 देने का झांसा

रजिस्ट्रेशन करा मोबाइल रिमोट पर लेकर वॉलेट से रुपए निकाल रहे ठग

मिसलेनियस लिंक पर कराते हैं रजिस्ट्रेशन, जिसके पीछे छिपी रहती है दूसरी वेबसाइट

मेरा पैसा

इंदौर • अविनाश रावत

कोरोना के कहर में नौकरी गंवा चुके युवाओं को अब प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 के नाम पर छला जा रहा है। उनसे 3500 रुपए प्रतिमाह भत्ता पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनसे वेबसाइट की लिंक पांच लोगों को वाट्सअप कराई जा रही है। जैसे युवा लिंक भेजते ही उनके मोबाइल रिमोट पर चले जाते हैं। और फिर शुरू हो जाता बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट से रुपए निकालने का सिलसिला। इंदौर सहित प्रदेशभर में सैकड़ों युवा बेरोजगारी भत्ता पाने के लालच में लाखों रुपए गंवा चुके हैं।

डीबी स्टार ने जब लोगों की शिकायत के आधार पर इसकी पड़ताल की तो पता चला, रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी रही लिंक सिर्फ डाटा इकट्ठा करने और लोगों के मोबाइल तक पहुंचने का जरिया मात्र है। ताना-बाना इस तरह बुना गया है कि देखते ही लोगों के मन में 3500 रुपए प्रतिमाह भत्ता पाने की लालसा जाग उठती है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का उपयोग किया गया है। डीबी स्टार ने साइबर एक्सपर्ट चाणक्य वाजपेयी और शोभित चतुर्वेदी से इस लिंक की हकीकत जानी। उनका कहना है कि यह एक तरह की miscellaneous लिंक है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए नाम, सरनेम, पता और अन्य जानकारियां सिर्फ दिखावे के लिए पूछी जाती हैं। आप गलत जानकारी भरकर भी आगे बढ़ सकते हैं। यह सब पांच लोगों तक लिंक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आप जैसे ही वाट्सअप या अन्य प्लेटफॉर्म से किसी को लिंक भेजेंगे, आपका मोबाइल रिमोट पर चला जाएगा। यानी मोबाइल का सारा डाटा, सभी एप हैकर्स के कंट्रोल में हो जाएंगे। इससे वह आपकी बैंक डिटेल निकालेगा। ओटीपी पढ़ेगा और खाता खाली कर देगा। आपकी फोनबुक का डाटा चुराकर बेच देगा।

लिंक पर क्लिक करने पर - 1

लिंक पर क्लिक करने पर प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना का पेज खुलता है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म- 2

पहले पेज में नीचे की तरफ यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है।

पांच लोगों को लिंक भेजना - 3

फॉर्म भरने के बाद बताई गई लिंक पांच लोगों को भेजने के लिए कहा जाता है।

3500 रुपए पाने के लालच में फंस में जाएं ऐसा जाल बिछाया है ठगों ने

प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 के तहत लोगों के जाल में फंसाने के लिए http://bit.ly/pradhanmantri-berozgaari-bhattaa-yojna लिंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ब्लॉगस्पॉट प्लेटफॉर्म पर https://pradhanmantri-berojgari-bhatta2020.blogspot.com/# लिंक बनाई गई है। इन पर क्लिक करते ही प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना नाम से पेज खुलेगा। योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित बताई गई है। नीचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, उम्र और राज्य आदि कॉलम हैं। फॉर्म भरने के बाद आगे बढ़ने पर तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, क्या आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा, आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और तीसरा, क्या आप पहले से किसी अन्य योजना भत्ते का लाभ ले रहे हैं? प्रश्नों जवाब देने पर नया पेज खुलता है। इसमें आपको योजना की पात्रता के लिए मुबारकबाद दी जाती है। साथ ही बताया जाता है कि आपको हर माह 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जिसे आप ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। पात्र सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपको यह लिंक वाट्सअप प्लेटफॉर्म पर पांच लोगों को भेजने के लिए कहा जाता है। जब तक इसे फारवर्ड नहीं करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। पांच लोगों को मैसेज भेजने पर एक नंबर बताया जाता है। अंग्रेजी के अक्षर और अंकों के योग वाला यह रजिस्ट्रेशन नंबर मात्र छलावा है।

झांसे में आकर किसी ने 1700 तो किसी ने 3700 रुपए गंवाए

इंदौर सहित प्रदेशभर में कई लोग इस योजना के फेर में फंस चुके हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके खातों से रुपए नहीं निकाले गए हैं, लेकिन उनके मोबाइल में अनजान एप्लीकेशन खुद-ब-खुद डाउनलोड हो गई। कॉल सेंटर में काम करने वाले नसीर खान बताते हैं कि वह नई नौकरी की तलाश कर रहे थे। किसी ने उन्हें वाट्सअप पर प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 की लिंक भेजी। उन्होंने उस लिंक पर रजिस्ट्रेशन किया और पांच दोस्तों को लिंक फारवर्ड कर दी। इसके दो दिन बाद उनके मोबाइल वॉलेट से 1700 रुपए निकाल लिए गए। अमाउंट छोटा था, इसलिए उन्होंने शिकायत नहीं की। इसी तरह अमरीश पोद्दार के खाते से 2500, हरीश मंगलावत के खाते से 3700 रुपए निकाल लिए गए हैं। कार्तिक पाण्डेय ने भी रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उनके खाते से रुपए नहीं निकाले गए। कार्तिक बताते हैं कि उनके मोबाइल में कई गेम और अनजान एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई हैं, जो डिलीट नहीं हो रही हैं।

ऐसी कोई योजना ही नहीं है

मप्र रोजगार बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर सीके बघेल बताते हैं कि बेरोजगारों को भत्ता देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2020 के नाम से कोई छलावा कर रहा है। यदि कोई योजना होती तो उसका क्रियान्वयन रोजगार बोर्ड के माध्यम से ही होता। मप्र शासन से ऐसा कोई पत्र नहीं आया है।

लोग हमें शिकायत भेजें, इससे पड़ताल करने में होगी आसानी

प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 के नाम से लोगों को miscellaneous लिंक भेजी जा रही है। यह bit.ly लिंक है। यानी इसके पीछे दूसरी वेबसाइट छिपी होती है। उसी से लोगों के मोबाइल रिमोट पर लेने के लिए यह जाल बिछाया जाता है। ठग लोगों के खातों से छोटी राशि निकाल रहे हैं ताकि वह इसकी शिकायत नहीं करें। हम लिंक ही छानबीन कर रहे हैं। जिनके साथ छलावा हुआ है, वह हमें शिकायत भेजें। इससे हमें पड़ताल करने में आसानी होगी।
जितेंद्र सिंह, एसपी स्टेट साइबर सेल

कोविड-19 | महामारी से पहले सिर्फ 5% लोग सही तरीके से हाथ धोते थे

सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते वक्त 60:20 का यह फॉर्मूला जरूर याद रखें

डा. विनोद रविंद्रन
कंसल्टेंट
र्‍यूमेटोलॉजिस्ट सेंटर
फॉर र्‍यूमेटोलॉजी
कालीकट, केरला

कोविड-19 से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूसरों से एक मीटर की दूरी रखने और हाथों की सफाई पर विशेष जोर दिया है। कोरोना वायरस से लड़ाई में सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमुख हथियार बताया है। इसके लिए साबुन और पानी से अक्सर हाथ धोने अथवा कम से कम 60 फीसदी अल्कोहलयुक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की बात कही है। डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं महामारी के इस काल में हाथों की सफाई पर विशेष जोर दे रही हैं। वहीं बड़े-बुजुर्गों ने भी हमेशा खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोने की सलाह दी है। इसीलिए, हाथों को साफ और कीटाणु रहित रखने के लिए यह एक पुरानी प्रथा रही है। लेकिन, वर्तमान में हम व्यस्त दिनचर्या के बीच हाथों की सफाई का उचित ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जानिए किस तरह का हैंड सैनिटाइजर कोरोना से लड़ने के लिए उचित है। उसका सही कम्पोजीशन क्या है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है।

कम से कम 60% अल्कोहल हो, 20 सेकंड तक हाथों में रगड़ें

सिर्फ हाथों को साफ रखकर कैसे अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं

21% तक सांस से जुड़े संक्रमणों का खतरा घट जाएगा, अगर हाथ साफ होंगे तो।

50% तक घट जाएगा डायरिया से जुड़े संक्रमण का खतरा, सही सफाई से।

कैसे काम करता है हैंड सैनिटाइजर

अल्कोहल में प्रोटीन और सूक्ष्मजीवों (जैसे कोविड-19 वायरस) को नष्ट करने व उनकी आंतरिक प्रणाली को बाधित करने की क्षमता होती है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा न्यूनतम 60% होनी चाहिए। अल्कोहल बेस्ड अधिकांश हैंड सैनिटाइजर में इथेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एन-प्रोपेनोल या इनमें से किसी दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। त्वचा को नुकसान से बचाने के लिए ग्लिसरीन मिक्स किया जाता है।

क्या है हाथ साफ करने की सही तकनीक

1
» कम से कम 3 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर को हथेली पर लें।

2 » 20-30 सेकंड तक अपने हाथों पर अच्छी तरह रगड़ें।

3
» कलाई के 2 सेमी तक का ऊपरी भाग भी शामिल हो। हाथों को सूखने के लिए छोड़ दें।

अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के उपयोग में यह करें

कम से कम 60 फीसदी अल्कोहल होना चाहिए। गंदे अथवा चिकनाईयुक्त हाथों में हैंड सैनिटाइजर अच्छे से काम नहीं करेगा। उन्हें साबुन और पानी से धोएं।

डब्ल्यूएचओ ने सैनिटाइजर के दो फॉर्मूले बताए हैं

डब्ल्यूएचओ के अनुसार सैनिटाइजर के दो फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला- जिसमें 80% तक इथेनॉल हो। 0.125% हाइड्रोजन पैराक्साइड और 1.45% ग्लिसराल हो। दूसरे फॉर्मूले के तहत इसमें इथेनॉल की जगह 75% आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो सकती है। बाकी घटक पहले फॉर्मूले की तरह ही बने रहेंगे।

- अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक- हाथों की सफाई से सांस से जुड़े संक्रमण का खतरा 21% तक घट जाता है।

स्वयं करके देखें : ऐसे घर पर बना सकते हैं डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर

The New York Times
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट अब न्यू नॉर्मल हैं। अब देश में लॉकडाउन से जुड़ी कई रियायतें मिल रही हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जानिए किस तरह आप घर में ही स्वयं के लिए डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं, जिससे जरूरी सतहों को साफ किया जा सकता है। साथ ही घर में असरदार सैनिटाइजर बनाया जा सकता है।

सैनिटाइजर : जानिए किस तरह कम लागत में आप इसे बना सकते हैं

मुहिमा हॉस्पिटल रवांडा के नर्सिंग प्रोग्राम के पूर्व डायरेक्टर जीन बॉस्को ब्यूकुसेनो ने घर में सैनिटाइजर बनाने का तरीका बताया है। बहुत कम लागत में 10 लीटर सैनिटाइजर बनाया जा सकता है।

क्या-क्या चाहिए: • 8.55 लीटर इथेनॉल • 417 मिली हाइड्रोजन पैराक्साइड • 145 मिली ग्लिसरॉल

कैसे बनाएं: कंटेनर अथवा प्लास्टिक जग में इथेनाल, हाइड्रोजन पैराक्साइड और ग्लिसरॉल मिला लें। अब शेष मात्रा में डिस्टलाइज वाटर अथवा उबालकर ठंडा किए गए पानी को अच्छी तरह मिक्स कर दें। आपका सैनिटाइजर तैयार है।

डिसइंफेक्टेंट : जिससे घर में कोरोना का खतरा घटा सकते हैं

- यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार घरों में इस्तेमाल होने वाली ब्लीच से नॉन पोरस सतह वाली चीजों पर जमा कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। सीडीसी के अनुसार एक चौथाई गैलन (3.7 लीटर पानी) में 4 टीस्पून ब्लीच मिलाई जानी चाहिए।
- इस मिक्सर को घर में अलग-अलग सतहों पर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के 10 मिनट बाद आप साफ कपड़े से सतह को साफ कर सकते हैं। स्रोत: सीएनएन